श्री राम चन्द्र विकल : मैं मांग रहा हूं डिसक्शन, आप इजाजत दीजिए ?

उपसभापति : आप उसके लिए पहले नोटिस तो दीजिए।

*162. [*The questioner (Shri M. Kadharsna) was absent. For answer,* vide *col.,* 31-34 *infra.*]

Management Information System for Urban Water Supply and Sanitation

*163. SHRI KAPIL VERMA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what steps Government have taken or propose to take to develop the Management Information System for Urban Water Supply and Sanitation;

(b) by when the National System is likely to be installed;

(c) the names of the places where this project is being implemented at present; and

(d) by when the Management Information System is likely to cover Lucknow and Kanpur cities of Uttar Pradesh?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) A project team has been constituted by the Ministry of Urban Development in October, 1986 for implementation of a pilot project for the development of Management Information System for community water supply and sanitation.

(b) This will depend on the time taken by the State agencits to furnish complete town-wise data on urban water supply and sanitation.

(c) The pilot project referred to above would be tested in Bhopal Division of Madhya Pradesh State comprising seven districts, namely, Bhopal, Raisen, Vidisha, Sehore; Betul; Rajgarh and Hoshangabad.

(d) No definite time limit can be indicated at present. However, on the basis of the reports of field testing & subsequent enhancement of the testing systems, if necessary and based on the recommendations of the project team, the computerised management information system be made available to other water, supply and sanitation agencies, including those in U.P. for their use.

SHRI KAPIL VERMA: Will the hon. Minister clarify the concept of Management Information Service, how it is going to work, whether it would be a cost-effective method of urban water supply and cover the meximum area?

श्री बलबीर सिंह : मैडम, मंत्रालय में 14 अक्तूबर, 1986 को यह निर्णय लिया गया कि अर्बन वाटर सप्लायो एंड सेनोटेशन यह दिन-प्रति-दिन बहुत प्राब्लम होतो जा रहो है इसलिए इसमें एक पायलट प्रोजैक्ट बनाया जाए और पूरी इसको कंप्यूटराइज माध्यम से इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसमें सब से पहले अभी मध्य प्रदेश में भोपाल डिवीजन को लिया गया है उसमें लगभग 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और उसके अंतर्गत 49 टाउन्स आते हैं। मैडम, इसलिए, भी यह बहुत आवश्यक है कि आज के हालात में भी हम डे-टू-डे वाटर टेबल और वाटर सप्लायी कितनी हो रही है उसको हम एक ही जगह से जान सकते हैं, इसमें चाहे डोमैस्टिक या इंडस्ट्रियल के लिए हो, हमारे कितने वाटर टेप्स हैं प्राइवेट हैं, कितनी पापुलेशन है हम इसको करने जा रहे हैं और जहां तक आशा है यह जो हमारा भोपाल में सब से पहला पायलट प्रोजैक्ट बनने जा रहा है अक्तूबर, 87 में कंप्लीट हो जाएगा।

SHRI KAPIL VERMA: What will be the main features of the national system mentioned in the statement? How is it going to work out and what is the target of the Government for covering all the States? Is the World Bank or any other financial instituion going to help in this?

श्री दलबीर सिंह : मैडम, सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान है और हमारे सारे हिन्दुस्तान में 3250 टाउन्स हैं। हमने स्टेट गवनमेंट्स को लिखा है कि सारे जितने भी हमारे टाउन्स हैं उनमें कितनी आबादी है उसकी आप रिपोर्ट भेजें। अभी तक हमें 1826 टाउन्ज जो हमारा वाटर सप्लायी का है उसकी इन्फर्मेशन आयी है और सीवरेज और सेनीटेशन के लिए 932 टाउन्ज की आई है। हम हर स्टेट में यही प्रोविजन करने जा रहे हैं कि जो बड़े टाउन्ज हैं उस स्टेट में एक ही जगह बैठकर हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारा वाटर टेबल कितना जा रहा है, पिछले साल कितना था और आगे आने वाले सालों में हमारी कितनी आबादी बढ़ेगी। तो इस सिस्टम में हमारे पास सातवीं पंचवर्षीय योजना एक करोड़ रुपया है जो हम सैन्ट्रल एसिस्टैंस देते हैं और पी.एच.डी. डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं हर स्टेट में ताकि इसकी जानकारी उनको पूरी हो और पूरा फीडबैक लोगों को मिले और साथ ही एक ही जगह से उन को सारी जानकारी मिल सके।

SHRI VISHWA BANDHU GUPTA: Madam, is the hon. Minister satisfied with the Management Information System with regard to water about Delhi and the sanitation in Delhi? If not, is this new system going to be applied to Delhi, is some improvement likely to be there in Delhi?

श्री दलबीर सिंह : मैडम, अभी जैसे मैंने बताया कि पायलेट प्रोजेक्ट का, सबसे पहले इसको हम भोपाल डिवीजन में कर रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट आनी है। यह तो सभी जगह लागू होगी, यह दिल्ली के लिए है, ऐसा नहीं है। यह हर स्टेट के लिए, हर यूनियन टेरीटोरी के लिए इसको लाग करेंगे।

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Madam, in the statement laid in response to the question, it has been stated that a project team has been constituted. And in part (b) it has been stated that it will depend on the time taken by the State agencies to furnish the town-wise data. I would like to know from the hon. Minister who are the members of the project team and whether any time limit has been fixed by the Government for the State agencies to furnish the complete town-wise data and whether Government has received any data from Bihar.

श्री दलबीर सिंह : मैडम, इसमें एक चेयरमैन हैं जो सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर हैं, 13 मेम्बर हैं और एक कन्वीनर है। इसमें अभी जैसा मैंने कहा, हम स्टेट गवर्नमेंट को इंफोरमेशन के लिए, जानकारी के लिए पत्र लगातार लिख रहे हैं, उनसे हम यह रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सारी अपनी प्रोजैक्ट दीजिए कि आपकी स्टेट में कितने टाऊन हैं और उन टाऊन में कितनी-कितनी आबादी है ताकि हम इसको परस्यू कर सकें।

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Whether any time limit has been fixed.

SHRI DALBIR SINGH: It depends upon information from State agencies.

SHRI RAJNI RAJAN SAHU: Whether the hon. Minister will assure that a time limit will be fixed.

श्री दलबीर सिंह : मैडम, मैं इसको इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि सारी स्टेट से हमारे पास इंफोरमेशन आ जानी चाहिए।

There are 3250 towns in the country and out of them we have received information about something like 1826 town. How can I say a time limit?

THE DEPUTY CHAIRMAN: It depends upon the information which they receive from the State Governments. How can he say that?

श्री बीर भद्र प्रताप सिंह : उपसभापति, महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उत्तर से हो यह निहित है कि बड़ा समय इसमें लिया जायेगा । अब हम इससे नाराज नहीं हैं कि मध्य प्रदेश के सात जिले हैं, आप मध्यप्रदेश के 20 ले लीजिए, मेरा यह निवेदन है मंत्री जी से । मगर हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ समस्यायें हैं शहरों की, कलकत्ता की एक समस्या है, बंबई की एक समस्या है, मद्रास की तीसरी समस्या है । तो आपने यह फरमाया कि टेस्टिंग हम बाद में शुरू करेंगे, जब राज्य सरकारों की रिपोर्ट आ जायेगी । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि क्या आप इस पर विचार करेंगे, सबसिक्वेंट इनेंहसमेंट जो आपने अपने उत्तर "डी" में लिखा है, इसके साथ ही क्यों नहीं मुख्तलिफ शहरों की आप टेस्टिंग करा लेते हैं, जिससे कि समय भी बचेगा ?

श्री बलबीर सिंह : मैडम, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं कि हम किसी टाऊन को छोड़ रहे हैं । जैसा कि हमने पहले ही कहा---3250 टाऊन कण्ट्री में हैं, उसकी हमको रिपोर्ट आनी है और मैं माननीय सदस्य को यह भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यह सबसे पहला कम्प्यूटराइज्ड पायलेट प्रोजैक्ट हमारा है, इसलिए हम देख रहे हैं कि फर्स्ट हमारा अक्तूबर में भोपाल में आता है । Later on, we will take all those towns. It is no problem.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 164, Shri Gurupadaswami. Absent. Dr. Bapu Kaldate. Absent. Question No. 165. Dr. Vijayamohan Reddy. Absent.

*164. [*The questions (Shri M. S. Gurupadaswamy and Dr. Bapu Kaldate were absent. For answer,* vide *col.*, 35 infra].

*165. [*The Questioner (Dr. G. Vajayamohan Reddy) was absent for answer,* vide *Col.*, 36-37 infra].

Urban Development in Madhya Pradesh

*166. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Central Government allocate funds for urban development in the States;

(b) if so, the financial assistance provided to Madhya Pradesh during the years 1985-86 and 1986-87 in this regard; and

(c) the places where such funds have been utilised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (c) An outlay of Rs. 1,640 lakhs and Rs. 1,850 lakhs had been provided for urban development in the annual plans of Madhya Pradesh during the years 1985-86 and 1986-87, respectively. Loan assistance was given to the State Government for the Integrate Development of Small & Medium Towns, as per statement laid on the Table of the House. [*See* Appendix CXLIII. Annexure No. 59]. Further, under the centrally sponsored scheme of Urban Basic Services, an amount of Rs. 2.76 lakhs has been released as grant-in-aid for the development of Indore, Mhow and Depalpur towns in Indore district. Funds to the